

- **हद्द:**
 - वर्ष 1955 में लागू हुए हद्द विवाह अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि **हद्द बहुविवाह को समाप्त कर दिया जाएगा और इसे अपराध बना दिया जाएगा**।
 - अधिनियम 1955 की धारा 11 में बहुविवाह को अमान्य घोषित किया गया है, अर्थात् **अधिनियम एकल विवाह को मान्यता प्रदान करता है**।
 - ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 17 के साथ-साथ **भारतीय दंड संहिता, 1860** की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाता है।
 - क्योंकि **बौद्ध, जैन और सखि** सभी हद्द माने जाते हैं और उनके अपने कानून नहीं हैं, इसलिए हद्द विवाह अधिनियम के प्रावधान इन तीनों धार्मिक संप्रदायों पर भी लागू होते हैं।
- **पारसी:**
 - **पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936** ने पहले ही **द्विविवाह को गैरकानूनी** घोषित कर दिया था।
 - कोई भी पारसी, व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीवनकाल में इस अधिनियम या किसी कसिी कसिी अन्य वधि के अधीन तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक कि उसने अपनी पत्नी या पति से वधिपूर्ण तलाक नहीं ले लेता। पत्नी या पति द्वारा कानूनी रूप से तलाक दिये बिना या उसकी पछिली शादी को अमान्य या भंग घोषित किये बिना भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदान किये गए दंड के अधीन है।
- **मुसलमि:**
 - **मुसलमि परसनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम** [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act] 1937 के तहत अखलि भारतीय मुसलमि परसनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदत्त खंड भारत में मुसलमानों पर लागू होते हैं।
 - **बहुविवाह मुसलमि कानून में नषिदिध नहीं है** क्योंकि इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए वे इस प्रथा को संरक्षति और सवीकार करते हैं।
 - फरि भी यह स्पष्ट है कि यद्यह तरीका **संवधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है**, तो इसे बदला जा सकता है।
 - जब भारतीय दंड संहिता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच असहमति होती है, तो **व्यक्तिगत कानूनों को लागू किया जाता है क्योंकि यह एक कानूनी सिद्धांत है** कि एक विशिष्ट कानून सामान्य कानून का स्थान लेता है।

बहुविवाह से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण:

- **परयांकंडियाल बनाम के. देवी और अन्य (1996):**
 - **सर्वोच्च न्यायालय** ने नषिकर्ष नकिला का एक विवाह वाले रशिते **हद्द समाज के मानक और वधिारधारा** थे, जो दूसरे विवाह की नदि और उसका तरिस्कार करते थे।
 - धर्म के प्रभाव के कारण बहुविवाह को **हद्द संस्कृति का अंग नहीं बनने** दिया गया।
- **बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अपपा माली (1951):**
 - बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि **बॉम्बे (हद्द द्विविवाह रोकथाम) अधिनियम, 1946 भेदभावपूर्ण नहीं था**।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि एक राज्य वधिायिका के पास लोक कल्याण और सुधार उपायों को लागू करने का अधिकार है, भले ही वह **हद्द धर्म या रीति-रिवाजों का उल्लंघन करता हो**।
- **जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि **स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव, गरिमा और कल्याण** अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं।
 - मुसलमि कानून चार महिलाओं से विवाह की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यह अनविार्य नहीं है।
 - यह चार महिलाओं से शादी नहीं करने के लिये धार्मिक प्रथा का उल्लंघन नहीं होगा।

भारतीय समाज और संवधानिक दृष्टिकोण में बहुविवाह:

- बहुविवाह का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसकी वैधता के लिये विशेष रूप से इस्लाम और हद्द जैसे- धर्मों के संबंध में **संवधानिक दृष्टिकोण से परचिर्चा की गई है**।
- भारत एक धर्मनरिपेक्ष देश है, जहाँ **कसिी भी धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ या अधीनस्थ नहीं माना जाता है, प्रत्येक धर्म** को वधि के तहत समान माना जाता है।
- भारतीय संवधान **सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों** की सुनिश्चिता प्रदान करता है, इन अधिकारों के विपरीत कसिी भी कानून को असंवधानिक माना जाता है।
- **संवधान का अनुच्छेद 13** नरिषिद करता है कि संवधान के भाग III का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा।
 - **आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970) मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **सैद्धांतिक दृष्टिकोण के घटक और राज्य का हस्तक्षेप, सुरक्षा की गंभीरता प्रकट करते हैं जो कि एक वंचित समूह** के लिये संवधानिक रूप से असंगत हो सकता है, जिसका उद्देश्य साधारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है।
- **संवधान का अनुच्छेद 14** भारत के राज्यक्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के तहत समान उपचार और सुरक्षा की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15(1) के अनुसार**, राज्य कसिी नागरिक के विरुद्ध उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर कोई वधिद नहीं करेगा।

इन देशों में बहुविवाह वैध है:

- भारत, सिगापुर, मलेशिया जैसे देशों में बहुविवाह विशेष रूप से केवल मुसलमानों के लिये अनुमत तथा वैध है।
- वर्तमान में **अल्जीरिया, मसिर तथा कैमरून** जैसे देशों में बहुविवाह मान्यता प्राप्त और प्रचलति है। केवल ये ही विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुविवाह वैध है।

नषिकरषः

- यह सच है कऱभारतीय समाज में बहुवविह लंबे समय से अस्तित्त्व में है और वर्तमान समय में अवैध होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में इसका प्रचलन है ।
- बहुवविह की प्रथा केवल कऱसी एक धरुम या संस्कृति से संबंघति नहीं है बल्कऱअतीत में इसे वभिन्न कारणों से उघति ठहराया गया है ।
- हालाँकऱसमाज के वकऱस के साथ बहुवविह का कोई औघतिय नहीं रह गया है और इस प्रथा का त्याग कर दऱया जाना चाहयि ।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्नः भारत के संवघान का कौन-सा अनुघुदेद अपनी पसंद के वयक्तऱसे वविह करने के कऱसी वयक्तऱके अधकऱर को संरकषण देता है?

- (a) अनुघुदेद 19
- (b) अनुघुदेद 21
- (c) अनुघुदेद 25
- (d) अनुघुदेद 29

उत्तरः (b)

वयख्याः

- वविह का अधकऱर भारत के संवघान के अनुघुदेद 21 के तहत जीवन के अधकऱर का एक घटक है, जसिमें कहा गया है कऱ"कानून द्वाऱा स्थापति प्रकुरिया के अलावा कऱसी भी वयक्तऱको उसके जीवन और वयक्तऱगित स्वतंत्रता से वंचति नहीं कऱया जाएगा" ।
- लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2006 में सर्वोघुच न्यायालय ने भारतीय संवघान के अनुघुदेद 21 के तहत वविह के अधकऱर को जीवन के अधकऱर के एक घटक के रूप में देखा ।

अतः वकिलुप (b) सही उत्तर है ।

??????????:

प्रश्नः रीत-रिवाजों एवं परंपराओं द्वाऱा तरुक को दबाने से प्रगतऱरिधि उत्पन्न हुआ है । कऱया आप इससे सहमत हैं? (2020)

सरोतः इंडयिन एक्सपरेस